

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक: 191/स.सा.प्र.वि./2020  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/04/2020

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त,
3. समस्त कलेक्टर,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,

**विषय:-** नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण बाबत।

- संदर्भ:-**
1. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक: 189/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 16/04/2020, एवं क्रमांक: 195/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 20/04/2020
  2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 15/04/2020, दिनांक 19/04/2020 एवं दिनांक 21/04/2020
  3. गृह सचिव, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 21/04/2020

—00—

संदर्भित आदेशों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत अधिकृत किया गया एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 21/04/2020 द्वारा कुछ अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है जिसके परिपेक्ष्य में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं।

2/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के अंतर्गत पैरा 6 A अंतर्गत कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी :-

ix. आयात/निर्यात हेतु पैकहाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं

x. कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान

xi. मधुमक्खी पालन के प्लान्टिंग मटेरियल, मधुमक्खी कॉलोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर परिवहन

3/ वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन के संबंध में पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के अंतर्गत पैरा 14 A निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी

xi. छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें

xii. बिजली के पंखे की दुकानें

4/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों अंतर्गत व्यक्तियों के आवागमन के बारे में पैरा 17 iii में भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के जहाजों पर आवागमन के संबंध में निर्धारित एसओपी अनुसार प्रावधान किया गया है।

5/ पूर्व में जारी समेकित निर्देशों में पैरा 19 v में वन कार्यालयों अंतर्गत वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

6/ स्पष्टीकरण – गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 21/04/2020 द्वारा पूर्व में जारी समेकित निर्देशों अंतर्गत कई गतिविधियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :-

i. सामाजिक क्षेत्र के पैरा 8 i में बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवायें दे रहे केयर गिवर सम्मिलित है।

ii. पब्लिक यूटिलिटी के पैरा 11 v में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल हैं।

iii. आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में पैरा 13 i में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फेक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है।

7/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संशोधित निर्देशों अनुसार प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

8/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

*KPI*  
22/4/20  
(डॉ. कमलप्रीत सिंह)  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

AJAY BHALLA, IAS



गृह सचिव  
Home Secretary  
भारत सरकार  
Government of India  
North Block,  
New Delhi

No. 40-3/2020-DM-I (A)

21<sup>st</sup> April, 2020

Dear Chief Secretary,

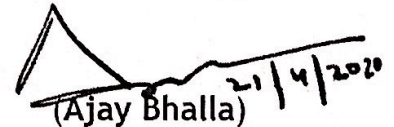
Kindly refer to consolidated revised guidelines issued by MHA's Order of even number dated 15<sup>th</sup> April, 2020, which was further modified vide Orders of even number dated 16<sup>th</sup> April, 2020 and 19<sup>th</sup> April, 2020.

2. Some queries have been received with regard to exemptions of specific services/activities within the categories already allowed in the guidelines issued under the above referred orders. In this regard, I would like to clarify that:-

- i. Social sector under clause 8(i) include bed side attendants and care givers of senior citizens residing in their homes.
  - ii. Public utilities under clause 11(v) include recharge facilities for prepaid mobile connection.
  - iii. Supply of essential goods under clause 13(i) include food processing units such as bread factories, milk processing plants, flour mills, dal mills etc. located in urban areas.
3. However, as specified in the lockdown measures, National COVID-19 Directives and Standard Operating Procedure for social distancing for offices, workshops, factories and establishments must be ensured.
4. District authorities and field agencies may please be informed on the above accordingly so as to avoid ambiguity at the ground level.

With regards,

Yours sincerely,

  
(Ajay Bhalla) 21/4/2020

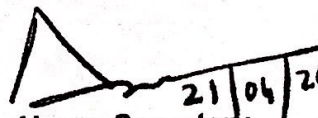
Chief Secretaries of All States  
(As per standard list)

North Block, New Delhi-110001  
Dated 21<sup>st</sup> April, 2020

**ORDER**

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 15<sup>th</sup> April, 2020, 16<sup>th</sup> April 2020 and 19<sup>th</sup> April 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders **to include** the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities:

- I. **Sub-clause (ix), (x) & (xi) under Clause 6 'A' on All Agricultural and horticultural activities:**
  - ix. Facilities for export/ import such as Pack houses, inspection and treatment facilities for seeds and horticulture produce.
  - x. Research Establishments dealing with the agriculture and horticulture activities.
  - xi. Inter and intra State movement of planting materials and honey bee colonies, honey and other beehive products.
- II. **Sub-clause (xi) and (xii) under Clause 14 on Commercial and private establishments:**
  - xi. Shops of educational books for students.
  - xii. Shops of electric fans.
- III. **Sub-clause (iii) under Clause 17 on Movement of persons:**
  - iii. Sign-on and sign-off of Indian Seafarers at Indian Ports and their movement for the aforesaid purpose as *per attached Standard Operating Protocol (SOP)*.
- IV. **Clause 19 (v) on Forest offices includes forestry plantation and related activities, including Silviculture operations.**

  
21/04/2020  
Home Secretary

To

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

(As per list attached)

Copy to:

1. All members of the National Executive Committee.
2. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

**Standard Operating Procedure (SoP) for sign-on and sign-off of Indian Seafarers at Indian Ports and their movement for the aforesaid purpose**

**[As per Ministry of Home Affairs (MHA) Order No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 21<sup>st</sup> April, 2020]**

Change of crew of ship (seafarers) is an important measure for operation of merchant ships. This SoP has been formulated to streamline the sign-on/sign-off of Indian Seafarer at Indian Ports for merchant shipping vessels. The following guidelines may be followed:

**I. For Sign-on**

- i. Ship owner/ Recruitment and Placement Service (RPS) agency will identify the Indian seafarers for joining a vessel.
- ii. The seafarers will intimate their travel and contact history for last 28 days to the ship owner /RPS agency by email, as per procedure laid down by Director General of Shipping (DGS).
- iii. The seafarer would be examined by a DGS approved medical examiner, as per the guidelines prescribed for this purpose. At the same time, the seafarer shall also be screened, and his travel and contact history examined for the last 28 days; seafarers found to be asymptomatic for COVID-19 and otherwise suitable may be processed for sign-on.
- iv. The local authority in the area where the seafarer resides will be intimated about his clearance for sign-on and for issue of a transit pass from the place of residence to the place of embarkation on the shipping vessel.
- v. The transit pass for such movement by road, for the seafarer and one driver, may be issued by the Government of the State/Union Territory where the seafarer resides.
- vi. The transit pass (to and fro) will be issued for a fixed route and with specified validity and will have to be adhered to strictly. Such transit pass would be honoured/ allowed by the authorities of the State/ Union Territory along the transit route.
- vii. The social distancing and other hygiene norms, as per standard health protocol, would be followed by the vehicle transporting the seafarer to his destination.
- viii. At the port of embarkation, the seafarer shall be tested for COVID-19; the seafarer would be ready for sign-on only if the COVID-19 test is negative, failing which, action as per guidelines of Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) would be taken.

**II. For Sign-off**

- i. The master of a vessel, coming from any foreign port, or a coastal vessel from any Indian port, while arriving at its port of call in India, shall ascertain the state of health of each person on board the vessel and submit the Maritime Declaration of Health to the health authorities of the port and to the port authorities. In addition, the information required by the local health authorities of the port, like temperature chart, individual health declaration, etc. shall also be provided by the master as per the directives of the health



authorities of the port. Port health authorities shall grant pratique to the vessel prior to berthing as per necessary health protocols.

- ii. The Indian seafarer arriving on the vessel would undergo the COVID-19 test for confirmation that he/ she is negative for COVID-19. After disembarking and till the time the seafarer reaches the testing facility, within the port premises, it will be ensured by the ship owner that all safety precautions as per standard health protocol are observed.
- iii. Till the time test reports of the seafarer are received, the seafarer shall be kept in the quarantine facility by the Port/ State Health Authorities.
- iv. If the seafarer is tested as positive for COVID-19, he/ she will be dealt with as per the procedures laid down by MoHFW.
- v. For the seafarer tested negative and signed off, the Local Authority in the area where the seafarer disembarks will be intimated about his/ her clearance for sign-off, and for issue of a transit pass from the place of disembarkation to the place of his/ her residence.
- vi. The transit pass for such movement by road, for the seafarer and one driver, may be issued by the Government of the State/Union Territory where the seafarer disembarks.
- vii. The transit pass (to and fro) will be issued for a fixed route and with specified validity and will have to be adhered to strictly. Such transit pass would be honoured/ allowed by the authorities of the State/ Union Territory along the transit route.
- viii. The social distancing and other hygiene norms, as per standard health protocol, would be followed by the vehicle transporting the seafarer to his destination.

**Note: DG (Shipping) will prescribe the detailed protocol with regard to sign-on and sign-off to be followed in the above cases.**

